

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से सामने आ रही घटनाएं एक बार फिर यह साबित कर रही हैं कि इस क्षेत्र पर इस्लामाबाद का नियंत्रण केवल सैन्य शक्ति, भय और दमन के बल पर कायम है. रावलकोट, पृष्ठ और अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, इंटरनेट बंदी और राजनीतिक असहमति को आतंकवाद के नाम पर कुचलने की कार्रवाई न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का भी खुला उल्लंघन है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर जो कड़ा रुख अपनाया है, वह परिस्थितियों के अनुरूप और आवश्यक है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिस स्पष्टता के साथ पाकिस्तान की पुलिस क्रूरता और बर्बरता की निंदा की है, वह केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की आवाज है जिन्हें वर्षों से अपने ही अधिकारों के

पीओके ; पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का समय

लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

पीओके में वर्तमान अशांति किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है. यह वहां के लोगों के भीतर वर्षों से जमा असंतोष का विस्फोट है. विधानसभा में 12 तथाकथित ‘शरणार्थी सीटों’ को लेकर स्थानीय जनता का विरोध इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान वहां की राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है. जिन लोगों का क्षेत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उनके माध्यम से सत्ता संरचना को प्रभावित करना जनता की राजनीतिक इच्छा का अपमान है.

इसके साथ ही महंगाई, बिजली संकट और आर्थिक उपेक्षा ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है. विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र से पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में पनबिजली प्राप्त होती है, वहीं के नागरिकों को महंगी बिजली और

बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है. यह संसाधनों के शोषण और जनता की उपेक्षा का स्पष्ट उदाहरण है.

सबसे गंभीर प्रश्न मानवाधिकारों का है. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना, विरोध करने वाले संगठनों को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित करना, इंटरनेट सेवाएं बंद करना और मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र की मूल भावना के विपरीत है. पाकिस्तान अवसर विश्व मंचों पर मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन पीओके में उसका व्यवहार उसकी दोहरी नीति को उजागर कर देता है.

भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की जो मांग की है, वह पूरी तरह उचित है. यदि दुनिया वास्तव में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक

मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे पीओके में हो रहे अत्याचारों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए जितनी वह अन्य क्षेत्रों के मामलों में दिखाती है. चयनात्मक संवेदनशीलता वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती है. सच्चाई यह है कि पीओके में उभर रहा जनक्रोश पाकिस्तान की प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक दमन का प्रत्यक्ष परिणाम है. गोली, गिरफ्तारी और संसरशिप के बल पर जनता की आकांक्षाओं को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता.

भारत का यह स्थायी और स्पष्ट रुख सही है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न हिस्सा है तथा पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है. अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस सच्चाई को स्वीकार करे और पीओके की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान पर ठोस दबाव बनाए.

ग्वालियर चंबल डायरी

प्राधिकरणों में कार्य विभाजन बना चुनौती, छत्रपों की ले रहे शरण



हरीश दुबे

प्राधिकरण स्वायत्तशासी हैं, लिहाजा इनके अध्यक्ष भी पूरीहंड हैं. नई नियुक्तियों के बाद इन प्राधिकरणों के कामकाज में फिलहाल तो कोई बाधा नहीं दिखती लेकिन भविष्य की अड़चन इन अध्यक्षों के साथ ही नियुक्त किए गए उपाध्यक्षों के कार्य विभाजन के दौरान आ सकती है. जीडीए में दो और साडा व मेला प्राधिकरण में एक एक उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं. ये सभी चार उपाध्यक्ष प्राधिकरण में महत्वपूर्ण कॉलोनियों से लेकर सीधे जनता व व्यापारियों से जुड़ाव वाली रसुखदार जिम्मेदारियां चाहते हैं. चूंकि अध्यक्षों के साथ ही उपाध्यक्ष भी सत्तारूढ़ दल के अलग अलग क्षत्रपों से ताकत हासिल करते हैं, लिहाजा कार्य विभाजन में ज्यादा से ज्यादा वजन हासिल करने की कवायद के लिए दिल्ली भोगाल तक दौड़ चल रही है. इधर, अशोक जादौन दिसंबर से शुरू होने वाले ग्वालियर व्यापार मेला की तैयारी में जुटे हैं तो मधुसूदन इस दीवाली तक शहर को बड़ी आवासीय योजना देना चाहते हैं जबकि अध्यक्ष शर्मा के समक्ष चुनौती साडा को हाशिए से उठकर मुख्य धारा में लाने की है.

मीनाक्षी के साथ खड़ी नजर आई चंबल की पूरी कांग्रेस

मीनाक्षी नटराजन एक दौर में जब एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और नेहरू युवा केंद्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे बड़े राजनीतिक रसूख वाले ओहदे संभाल रही थीं, तभी से ग्वालियर चंबल अंचल से उनका भावनात्मक लगाव रहा है. उन्होंने यहां के कई नेताओं को अपनी टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उन्हें

राष्ट्रीय पहचान दिलाई. यही वजह है कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने जब उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया तो इस अंचल में खूब जश्न मना और जब उनका नामांकन रह हुआ तो उनके गृहक्षेत्र मंदसौर रत्नाम के बाद जिस इलाके के कांग्रेसजर्न सर्वाधिक गम में डूबे हैं तो वह ग्वालियर चंबल क्षेत्र है. मीनाक्षी का नामांकन रह होने के विरोध में आज चंबल अंचल के हरेक शहर में हुए विरोध प्रदर्शनों में जिस तरह जिस तरह कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी और आक्रोश छलका, उससे जाहिर है कि उन्हें भले ही पार्टी में भीड़ जुटाने वाली नेता न माना जाता रहा हो लेकिन सांगठनिक स्तर पर उनका कोई शानी नहीं है. जब ग्वालियर में एनएसयूआई और युका में पदाधिकारी ऊपर से थोपने के बजाए पहली बार चुनाव के जरिए चयन की परिपाटी शुरू हुई तो उन्होंने इसकी सीधी मॉनिटरिंग की थी. चंबल में उनके मुरोंदों को फिलहाल दिलरी से आने वाले चुनाव आयोग के अगले आदेश का इंतजार है.

मंत्री के साथ मंच साझा कर मुसीबत में पाषंदपति आसिफ अली

कांग्रेस नेता और पाषंदपति आसिफ अली खान को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के साथ मंच साझा करना महंगा पड़ गया है. जनप्रतिनिधि के तत्ता ऊर्जा मंत्री के साथ उनके मंच पर बैठने में कांग्रेस अनुशासन समिति को ज्यादा एतराज नहीं है लेकिन इल्जाम यह है कि जब मंत्री महोदय मंच से कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले कर रहे थे, तब आसिफ अली चुप्पी लगाकर बैद गए. इससे पहले भी आसिफ अली कांग्रेस संगठन में पदों के बंटवारे में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखे जाने का इल्जाम लगाकर किसी तरह बच निकले थे लेकिन इस बार अनुशासन समिति उनके प्रति कुछ ज्यादा ही तल्ख है. उन्हें नोटिस थमा दिया गया है, जिसका जवाब आसिफ ने यह कहते हुए दिया है कि उन्होंने तत्काल ही एक प्रेस रिलीज जारी कर ऊर्जा मंत्री के इल्जामों पर नाराजगी के साथ नाइतफाकी जता दी थी. बहरहाल, कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर फैसला अनुशासन समिति ने होल्ड पर रखा है.

निकाय चुनाव से पहले महिला मोर्चा में पूरे घर के बदले

अंततः करुणा सक्सेना भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षी पाने में कामयाब रही हैं. खैतरटे की डिग्रीधारी करुणा को स्थानीय पार्टी संगठन में सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिला नेत्रियों में शुमार किया जाता है. वे अभी तक जिला महामंत्री थीं और अब उन्हें प्रमोशन मिला है. हालांकि एक और जिला महामंत्री किरणलता भदौरिया भी रसधा में थीं. ममता भिलवार का भी नाम भी चल रहा था लेकिन टॉटरी करुणा सक्सेना के नाम की खुली. अभी तक नीलिमा शिन्दे जिलाध्यक्ष पद संभाल रही थीं. पार्टी निवर्तमान पदाधिकारियों नीलिमा और किरणलता को संगठन में अन्य कहीं एडजस्ट कर सकती है. खास बात यह कि नई अध्यक्ष करुणा सक्सेना और पुरानी अध्यक्ष नीलिमा ने अपना राजनीतिक कैरियर ग्वालियर निगम में पाषंदी से शुरू किया था और बाद में महिला मोर्चा में जिला नेतृत्व तक पहुंची. सिर्फ ग्वालियर ही नहीं बल्कि अंचल के मुरैना, शिरपुरी, श्योपुरी और अशोकनगर में भी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बदल दी गई हैं. चूंकि निकाय चुनाव नजदीक है और टिकट वितरण में महिला मोर्चा की अनुशांसा भी मायने रखती है, लिहाजा इन नियुक्तियों को महत्पूर्ण माना जा रहा है.



पीयूष गौयल

वर्ष 2014 के बाद से, भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है. इसकी अर्थव्यवस्था कहीं अधिक मजबूत हुई है. बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से बेहतर हुआ है. महिलाएं बेहद

सशक्त हुई हैं. किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और गरीब अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हुए हैं. इन तमाम बदलावों में एक ही बात साझा है- प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और उनका नेतृत्व.

भारत के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व का भरपूर समर्थन किया है और उन्हें देश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बनाया है. बीते 10 जून को उन्होंने राष्ट्र की सेवा में 4,399 दिन पूरे किए और अपनी पहली चुनावी जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए.

यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. देश के लोगों ने ऐसे समय में 2014 में मोदी सरकार को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और यूएिए सरकार के बदनाम कार्यकाल के दौरान नीतिगत गतिरोध, भ्रष्टाचार, घोटालों एवं विवादों को लेकर जनता में निराशा लगातार

आधुनिक बुनियादी ढांचा

मोदी सरकार देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से बदलाव ला रही है. सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है. वर्ष 2014 में सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 74 थी और अब यह 160 से अधिक हो गई है. बड़े पैमाने पर रेलवे के विद्युतीकरण, महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने देश के कई हिस्सों के बुनियादी ढांचे को दुनिया के बेहतरीन बुनियादी ढांचों की बराबरी में ला खड़ा किया है. प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का वास्तविक महत्व कार्यकाल के दिनों की गिनती में नहीं, बल्कि किए गए व्यापक बदलावों में निहित है. उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने गरीबों एवं किसानों के कल्याण, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को शासन के केंद्र में रखा है. अब जबकि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण के नए संकल्प के साथ बदलाव की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी.

बढ़ रही थी.

संवेदनशील नेतृत्व- 2014 से देश निरंतर बदलाव की या